

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या-277 / 2024

अन्तर्गत

अपील संख्या-2495 / 2024

मंजू गुप्ता

—प्रार्थी—अपीलार्थी

बनाम

- श्रीमती गायत्री ए.राठौड़, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- राकेश कुमार शर्मा, निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।

—अप्रार्थीगण—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 27.08.2025

उपस्थित :-

प्रार्थी—अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
अप्रार्थीगण—प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

- प्रार्थी—अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण—प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के अपील संख्या 2495 / 2024 में दिनांक 08.11.2024 को पारित आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की गई है। अधिकरण के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 08.11.2024 का प्रभावी भाग (Operating Part) निम्न प्रकार है :-

“हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने प्रथम विकल्प अलवर जिले का दिया था, अपीलार्थी को अलवर जिले में पदस्थापन न कर अपीलार्थी ने कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का अलवर जिले में पदस्थापित किया गया है। उक्त स्थिति के दृष्टिगत अपील प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को उसके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार रिक्त पद होने की स्थिति में पदस्थापित किया जावे। इस आदेश की पालना एक माह में किया जाना सुनिश्चित करे। उक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।”

- उनका आगे अभिकथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 08.11.2024 की बिना उचित कारण के जानबूझ कर अवहेलना की जा रही है, जो कि माननीय अधिकरण के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अधिकरण के आदेश की पालना किए जाने के संबंध में प्रतिवेदन दिनांक 13.11.2024 प्रस्तुत किया। उक्त प्रतिवेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है। अतः बिना उचित

कारण के जानबूझ कर अधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। प्रत्यर्थागण जानबूझ कर अधिकरण के आदेश की पालना नहीं कर रहा है। इसलिए प्रत्यर्था विभाग माननीय अधिकरण के आदेशों की अवहेलना के दोषी है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रत्यर्था विभाग से माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 08.11.2024 की पालना करवायी जावे और पालना नहीं करने की स्थिति में प्रत्यर्था विभाग के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ कर माननीय उच्च न्यायालय को दण्ड हेतु रैफर किया जावे।

3. अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थागण की ओर से अवमानना याचिका का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2024 की पालनार्थ में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था के माध्यम से माह जून 2024 में नवचयनित अभ्यर्थी जिनके माह जुलाई 2024 में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पदस्थापन आदेश जारी किये गये थे के संबंध में स्पष्ट स्थिति यह है कि उक्त पदस्थापन रोस्टर/मेरिट/विकल्प के आधार पर किये गये हैं जिसके संबंध में समस्त नवनियुक्त अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा आदेश दिनांक 21.06.2024 द्वारा सूचित किया गया था। आदेश के साथ इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे जिसमें बिन्दु संख्या 6 पर "पदस्थापन स्थान आवंटन पूर्णतया रोस्टर कम मेरिट/विकल्प आधार पर काउन्सलिंग के माध्यम से किया जायेगा" एवं बिन्दु संख्या 7 पर "अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम विकल्प भरने के संबंध में कोई सीमा नहीं है। वह प्रदर्शित हो रही समस्त रिक्तियों का विकल्प भी अंकित कर सकता है। चूंकि विकल्प के आधार पर पदस्थापन स्थान का आवंटन रोस्टर कम मेरिट के अनुसार होगा। अतः अभ्यर्थी को अधिकाधिक विकल्प भरने की सलाह दी जाती है।" विभाग द्वारा पोर्टल पर अलवर जिले के कुल 58 रिक्त पद समस्त अभ्यर्थियों को विकल्प अंकित करने हेतु प्रदर्शित किये गये थे। उक्त पदों में अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना में अंकित रिक्त पदों यथा सामान्य चिकित्सालय अलवर एवं जिला क्षय रोग निवारण केन्द्र अलवर के रिक्त पद विभागीय प्राथमिकताओं के दृष्टिगत प्रदर्शित नहीं किये गये थे अर्थात् उक्त पद हेतु किसी भी अभ्यर्थी को विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं करवाये गये थे। अपीलार्थी का चयन अनारक्षित श्रेणी में किया गया है एवं इनकी मेरिट क्रमांक 851 है। उसके द्वारा आदेश दिनांक 21.06.2024 में स्पष्ट निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी पूरे राज्य में प्रदर्शित 1794 रिक्त पदों में से मात्र 56 पदों का ऑनलाईन

विकल्प प्रस्तुत किया गया जिसमें अलवर जिले में प्रदर्शित 58 में से मात्र 01 विकल्प (सैटेलाईट चिकित्सालय काला कुआ, अलवर) का प्रथम वरीयता के रूप में अंकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा भरे गये 56 विकल्प में से चतुर्थ वरियता पर पीएचसी पारलू बालोतरा का विकल्प प्रस्तुत किया गया। ऑनलाईन आवंटन में अपीलार्थी को उनकी वरीयतानुसार पीएचसी पारलू बालोतरा आवंटित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिक्त पदों का विकल्प किसी अभ्यर्थी को अंकन हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम एवं अलवर जिले के एक मात्र विकल्प पर श्री अभिषेक शर्मा जिनका चयन भी अनारक्षित श्रेणी में हुआ है एवं मेरिट क्रमांक 64 है (अनुलग्नक-आर/1), का पदस्थापन किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दिये गये दूसरे व तीसरे विकल्प पर अपीलार्थी से उपर ओबीसी की मेरिट क्रमांक 141 एवं 322 पर सुरेन्द्र पाल चौधरी एवं उदय कुमावत को पदस्थापित किया गया है (अनुलग्नक-आर/2)। अपीलार्थी की मेरिट संख्या 851 है, इससे स्पष्ट है कि अभ्यर्थिया द्वारा अलवर जिले में प्रस्तुत किये गये विकल्पों में से किसी स्थान पर उनसे मेरिट में नीचे आने वाले अभ्यर्थी का पदस्थापन ऑनलाईन आवंटन के द्वारा नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी अलवर जिले में 58 प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध मात्र 01 विकल्प प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थी द्वारा भरे गये 56 विकल्पों में से चतुर्थ वरीयता पर पीएचसी पारलू बालोतरा मेरिट एवं विकल्प के आधार पर आवंटित किया गया। पदस्थापन प्रक्रिया के दौरान तत्समय अलवर जिले में प्रदर्शित समस्त 58 रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों का पदस्थापन किया जा चुका है (अनुलग्नक-आर/3)। अपीलार्थी के प्रकरण में उनके द्वारा अलवर जिले में तत्समय भरे गये ऑनलाईन विकल्प अनुसार चिकित्सा संस्थानों में पद रिक्त नही होने के कारण कार्यवाही की जानी संभव नहीं है।

4. हमनें उभय पक्षकारों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी-अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अवमानना प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपने जवाब के तथ्यों की पुनरावृत्ति की। हम पाते है कि अधिकरण का आदेश पारित हुए करीब 9 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु अधिकरण के आदेशों की पालना नहीं की गयी है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिकरण के आदेशों की पालना न कर लगातार अवमानना की जा रही है।

5. स्वीकृत रूप से अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2024 के क्रियाशील भाग में यह अंकित किया गया है कि :-

“हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने प्रथम विकल्प अलवर जिले का दिया था, अपीलार्थी को अलवर जिले में पदस्थापन न कर अपीलार्थी ने कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का अलवर जिले में पदस्थापित किया गया है। उक्त स्थिति के दृष्टिगत अपील प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को उसके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार रिक्त पद होने की स्थिति में पदस्थापित किया जावे। इस आदेश की पालना एक माह में किया जाना सुनिश्चित करे। उक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।”

6. यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अधिकरण ने प्रार्थी-अपीलार्थी की पूर्वोक्त अपील में आदेश पारित कर अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण ने अभी तक नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण के लिये यह आवश्यक था कि वे अधिकरण के आदेश की समयावधि में पालना करते या माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्रियान्विति पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त करते। प्रिवी काउन्सिल के सर लॉरेन्स जेनकिन्स ने जसकर्ण बोइद बनाम पिरथीचन्द लाल (ए.आई.आर. 1918 पी.सी. 151) के प्रकरण में निम्न प्रकार अवधारित किया था :-

"whatever be the theory under other systems of law, under the Indian law and procedure an original decree is not suspended by the presentation of an appeal nor is its operation interrupted where the decree on appeal is merely one of dismissal. There is nothing in the Indian law to warrant the suggestion that the decree or order of the court or tribunal of the first instance becomes final only on the termination of all proceedings by way of appeal or revision."

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह (ए.आई. आर. 1958 एस.सी. 86) में प्रिवी काउंसिल के पूर्वोक्त निर्णय का अनुमोदन करते हुए निम्न मत व्यक्त किया था :-

"the filing of an appeal might put the decree or order in jeopardy but until it is reversed or modified it remains effective."

8. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.डी.देसाई ने हंसराज धीर के प्रकरण (1985 Cri. L.J. 1030) में अवमानना प्रकरण के सिद्धान्तों की निम्न प्रकार व्याख्या की थी :-

"Once a case is decided, it is the bounden duty of the State and its subordinates to implement, with the utmost expedition, the said decision. In a Government which is ruled by law, there must be complete awareness to carry out faithfully and honestly the decisions rendered by courts of law after

effective adjudication. Then only will private individuals, organisations and institutions learn to respect the decisions of courts. In absence of such attitude on the part of all concerned, chaotic conditions might arise and the functions assigned to the courts of law under the Constitution might be rendered a futile exercise. It requires to be emphasised, in this connection, that mere preferment of an appeal does not automatically operate as a stay of the decision under appeal and that till an application for stay is moved and granted by the appellate court, or, in the alternative, the court which rendered the decision is moved and grants an interim stay of the decision pending the preferment of an appeal and grant of stay by the appellate court, the decision continues to be operative. Indeed, non-compliance with the decision on the mere ground that an appeal is contemplated to be preferred or is actually preferred, and that, therefore, the matter is subjudice, may amount to contempt of court punishable under the Contempt of Courts Act, 1971."

9. उपर्युक्त विनिश्चयों के आलोक में और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विनम्र मतानुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण ने इस अधिकरण के आदेश दिनांक 08.11.2024 की पालना न कर उक्त न्यायिक आदेश की अवमानना कारित की है। हम इस अवमानना प्रकरण को अधिकरण में लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं और इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 10 के प्रावधान के क्रम में उपर्युक्त अवमानना कृत्य के लिए अवमाननाकर्ताओं के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु संदर्भित करना उचित समझते हैं।
10. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी-अपीलार्थी के अवमानना प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर को संदर्भित करावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष